क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 247, मंगलवार, 02 अक्टूबर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

2 अक्टूबर: लाल बहादुर शास्त्री जयंती कल, पढ़ें उनका जीवन परिचय

नई दिल्ली। कल देश गांधी जयंती के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक शांत चित्त व्यक्तित्व भी थे। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हुआ था। वह अपने घर में सबसे छोटे थे तो उन्हें प्यार से नन्हें बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था।

मुश्किल परिस्थितियों हासिल की शिक्षा-

बचपन में ही पिता की मौत होने के कारण नन्हें अपनी मां के साथ नाना के यहां मिर्जापुर चले गए। यहीं पर ही उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वह नदी तैरकर रोज स्कूल जाया करते थे। क्योंकि जब बहुत कम गांवों में ही स्कूल होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे। शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ। जिनसे दो बेटियां और चार बेटे हुए। एक बेटे का नाम अनिल शास्त्री है जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। देश के अन्य नेताओं की भांति शास्त्री जी में भी देश को आजाद कराने की ललक थी लिहाजा वह 1920 में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने 1921 के गांधी से असहयोग आंदोलन से लेकर कर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ों आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और पुलिसिया कार्रवाई का शिकार बने।

दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा

शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों महत्व बताने के लिए उन्होंने 'जय जवान जय किसान' का नारा भी दिया। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री की मौत ताशकंद समझौत के दौरान रहस्यमय तरीके से हो गई।

वैज्ञानिकों ने जानी राजयोग मेडिटेशन की गहराईयां

नई दिल्ली। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के स्पार्क विंग के तत्वावधान में वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के लिये विशेष रूप से तैयार एक डायलॉग प्रोग्राम 'इन्फार्मेशन, नॉलेज एंड विजडम' का आयोजन गुरूग्राम स्थित ओम् शान्ति रिट्रीट सेंटर पर किया गया । इसमें देश के नामी ग्रामी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव विकास में उसकी आंतरिक शक्तियों की भूमिका एवं उनके प्रयोग पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। राजयोग मेडिटेशन के आधार पर किस प्रकार से संपूर्ण विश्व में शांति एवं खुशी लाई जा सकती है इसको व्यावहारिक उदाहरणों के तौर पर प्रस्तुत किया गया।

ओम् शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा नेइन्फोर्मेशन, नॉलेज एवं विजडम के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा कि इन्फार्मेशन एवं नॉलेज प्रकृति प्रदत्पत नहीं आपितु मानव द्वारा बाहरी वातावरण से अर्जित किए जाते हैं वह जब अपनी आंतरिक शक्तियों जो उसके मूल गुण हैं का प्रयोग कर जब अपनी नॉलेज को व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करता है तो वह विजडम कहलाती है। जो बात सत्य है उसको वैसा ही जानना और समझना विजडम है। इसमें राजयोग मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा हम पहले स्वयं से जुड़ते हैं तथा खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं । राजयोग हमें सर्वशक्तियों के सुप्रीम सोर्स यानि परमात्मा से जुड़ना सिखा देता है जहां से हमें विजडम प्राप्त होती है। विजडम से जुड़ते ही आंतरिक शक्तियों व गुणों का विकास होता है और सकारात्मकता हमारे सम्बन्धों में तथा वातावरण में भी परिवर्तन लाती है। सरोज ने आपने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए ब्रह्माकुमारीज संस्था की गतिविधियों से अवगत करवाया और राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति करवायी। उन्होंने भविष्य में भी स्पार्क विंग द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग राजयोग से लाभांवित हो सकें।

वर्ल्ड पीस मानुमेंट

पूना स्थित पृवी का सबसे विशाल खंभारहित गुम्बद (वर्ल्ड पीस मानुमेंट) बिना किसी प्रोफेशनल वास्तुकार की मदद लिए डिजाइन किया गया है। इस गुम्बद में मानवता की 54 महान हस्थियों की कांस्य प्रतिमाएं संरक्षित की जाएंगी।

रेप के आरोपी दाती महाराज के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शिष्या से यौन शोषण मामले में स्वयंभू बाबा दाती मदन महाराज के खिलाफ सोमवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाती मदन महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, बीते 7 जून को पीड़िता ने दाती महाराज के खिलाफ दिल्ली के फतेपुर बेरी थाने में बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसी इलाके के असोला गांव में शनिधाम है जिसकी स्थापना दाती महाराज ने की थी।

पीड़िता ने शिकायत में पुलिस को बताया कि उसके साथ पहले दाती ने दिल्ली के आश्रम में बलात्कार किया फिर राजस्थान के आश्रम में। इस शिकायत में पीड़िता ने बाबा के दो और भक्तों का नाम भी दिया। उन भक्तों पर भी यौन शोषण का आरोप है।

मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगने के बाद यह मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। इस मामले में आरोपी दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, छेड़खानी जैसे जघन्य अपराधों को लेकर प्राथमिकी दर्ज है।

किसानों के मार्च को देख सतर्क हुई पुलिस, एक सप्ताह के लिए पूर्वी दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले हरिद्वार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हजारों किसानों के मंगलवार को यहां पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पंकज सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया जो आठ अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के अंतर्गत प्रीत विहार, जगतपुरी, शकरपुर, मधु विहार, गाजीपुर, मयूर विहार, मंडावली, पांडव नगर, कल्याणपुरी और न्यू अशोक नगर पुलिस थानाक्षेत्र आते हैं।

चुनाव आयोग की मदद करेंगी सोशल मीडिया कंपनियां कर्नाटक चुनाव में हुआ था परीक्षण

अब फेसबुक, ट्विटर पर फर्जी खबरें नहीं

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों ट्विटर और फेसबुक ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि प्रचार के दौरान चुनाव की शुचिता को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज के लिए वह अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रावत ने कहा, कर्नाटक चुनाव के दौरान इसका परीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा, तब छोटी पायलट परियोजना के तौर पर इसे लागू किया गया। वह शुरुआत थी। अब लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बड़े स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। इन चारों राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

रावत ने कहा, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में एक समिति ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के क्षेत्रीय और स्थानीय प्रमुखों को बुलाया था और उनसे पूछा था कि फर्जी खबरों के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और मतदाताओं को लक्षित कर डाले गए संदेशों से बचने के साथ भारतीय चुनाव की शुचिता के लिए वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, उन सभी ने प्रतिबद्धता जताई है कि प्रचार अवधि के दौरान और मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटे के दौरान वह ऐसी कोई चीज नहीं होने देंगे जो इन प्लेटफॉर्मों पर समान अवसर दिए जाने की प्रक्रिया पर विपरीत असर डालती हो।

उन्होंने वादा किया है कि चुनाव से जुड़ा कुछ भी उनके प्लेटफॉर्मों पर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, उक्त कंपनियों ने आयोग को यह भरोसा भी दिलाया है कि राजनीतिक विज्ञापनों के साथ उन पर खर्च राशि का ब्योरा भी होगा ताकि प्रचार अवधि के दौरान के व्यय का हिसाब लगाया जा सके। गूगल एक ऐसी पग्राली तैयार करेगी जिससे यह अपने प्लेटफॉर्मों पर खर्च के बारे में डाली गई जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा कर सके।

मीडिया प्लेटफॉर्मों के विस्तार और विविधता को देखते हुए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 में संभावित बदलावों पर विचार करने के लिए सिन्हा के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था।

नफरत और हिंसा फैलाने में एक जैसे हैं पाकिस्तान और आरएसएस : कांग्रेस

एजेंसी,नागपुर। कांग्रेस कार्यसमिति की महाराष्ट्र के वर्धा में होने वाली बैठक से एक दिन पहले पार्टी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एवं पाकिस्तान 'नफरत, हिंसा फैलाने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने में एक जैसे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस 'दलितों-पिछड़ों का दमन तथा प्रजातंत्र का हनन करने वाली भाजपा सरकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को मुक्ति दिलाने के लिये तैयार हैं।

उन्होने संवाददाताओं से कहा, '' जब गांधी जी और कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो आरएसएस खामोश था। आरएसएस समाज के किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह हिंसा में विश्वास करता है और उसका आधार ध्रुवीकरण, घृणा और विभाजन है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आरएसएस विरोधी बयान से जुड़ी खबर पर सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ''आरएसएस की तरह पाकिस्तान भी हिंसा का समर्थन करता है और वह नफरत और विभाजन का सहारा लेता है। कांग्रेस और भारत की जनता इसका समर्थन नहीं करती हैं।

सुरजेवाला ने कहा, ''राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, महात्मा गाँधी के मार्ग पर चल कर, देश को आर्थिक अराजकता, किसानों के दमन, भ्रष्टाचारी, बैंक लूट, घोटालों व राफेल के घोटालेबाजों, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, दलितों-पिछड़ों का दमन तथा प्रजातंत्र का हनन करने वाली 'भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाने के लिये तैयार है।'' उन्होंने कहा, '' अंग्रेजी हुकूमत भी भारत के संसाधनों को लूट कर विदेश ले जाती थी। भाजपा सरकार भी भारत के 'बैंक लुटेरों को विदेश भागने की खुली छूट देकर भारत के संसाधनों पर डाका डाल रही है ।'' उन्होंने कहा, ''अंग्रेजी हुकूमत भी भारत के बहुलतावाद को कुचल कर 'फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए हुए थी। भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक-जातीय-क्षेत्रीय बंटवारे और ध्रुवीकरण के बीज बोकर 'शकुनि की भांति हर हालत में सत्ता प्राप्ति के लिए 'राजनैतिक चौसर खेल रही है।''

उन्होंने आरोप लगाया, ''अंग्रेजी हुकूमत भी चंपारण में नील का 'तीन कठिया कानून बनाकर किसानों का दमन करती थी। भाजपा सरकार भी किसानों को फसलों के दाम न देकर 'आत्महत्या की ड्योढ़ी पर जबरन पहुंचाती है और न्याय मांगने पर किसान के 'सीने में गोलियां उतार देती है ।'' उन्होंने कहा, ''अंग्रेजी हुकूमत भी समाज की 'अंतिम पंक्ति के लोगों का शोषण कर गुलामी की जंजीरों में धकेलती थी। बीजेपी सरकार का 'डीएनए भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के शोषण एवं प्रताड़ना वाला है।

सुरजेवाला ने कहा, ''अंग्रेजी हुकूमत भी नमक का 'काला कानून बना कर भारत के नागरिकों को भारी भरकम करों के बोझ तले दबाती थी। भाजपा सरकार भी 'गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) और नोटबन्दी जैसे मनमाने फैसले थोप कर आम नागरिक और छोटे-छोटे दुकानदार तथा व्यवसायियों की रोजी रोटी पर कुठाराघात करती है।'' उन्होंने दावा किया, ''अंग्रेजी हुकूमत भी 'मुट्ठी भर अमीरों और 'जमींदारों के हितों को साधकर अपना शासन चलाती थी। मोदी सरकार भी 'मुट्ठी भर अमीरों और सरमायादारों के लिए काम कर रही है और गरीब के अधिकार छीन कर, भारत के संसाधनों को अपने मुट्ठी भर अमीर दोस्तों पर लुटा रही है।''

केजरीवाल के खिलाफ तिलक नगर थाने में शिकायत

नई दिल्ली। लखनऊ में एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर दिए गए बयान को आधार बनाकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी है। केजरीवाल के ट्विटर पर दिए गए बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल ने धर्म के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा दिया और 125 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया।

देश के शहीद सैनिकों को समर्पित है ट्रांस हिमालय की यात्रा

6500 किमी का सफर व्हील चेयर से करेंगे दिव्यांग

नई दिल्ली, एजेंसी। पैरा एथलीट और लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस में तीन कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी एरिक पॉल ने ट्रांस हिमालय अभियान के तहत अपनी यात्रा की शुरु आत रविवार को महापौर निवास 1 लांसर्स रोड तिमारपुर से की। वह करीब 6500 किमी लंबी यात्रा व्हील चेयर के जरिए पूरी करेंगे। यह यात्रा उत्तरी दिल्ली के महापौर आदेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ ही एरिक ने साबित किया है कि विकलांगता शरीर में नहीं दिमाग में होती है। महापौर ने कहा कि एरिक पॉल इस अभियान को हमारे देश के बहादुर सैनिकों को समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और शहीद हो गए। उन्होंने कहा की इस तरह की पहल से युवा सेना और अन्य सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वहीं एरिक पॉल ने कहा कि मेरी यात्रा देश के उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं।

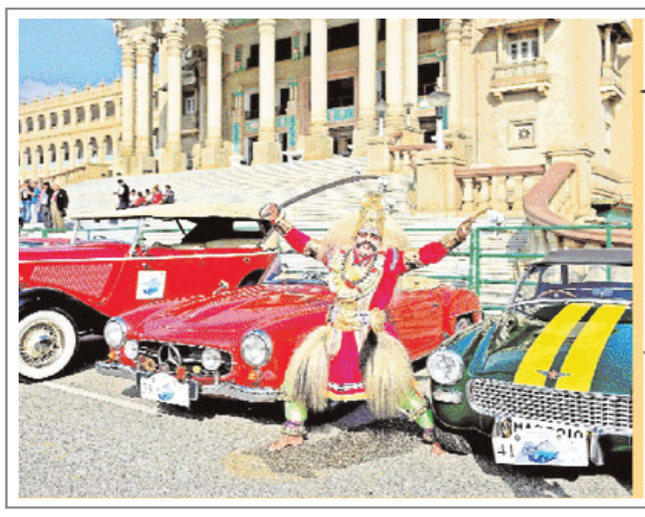

बेंगलुरु में रविवार को हेरिटेज, विंटेज एंड रॉयल क्लासिक कार ड्राइव शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम पेश करता एक कलाकार।

नारी सशक्त होगी तो समाज संगठित होगा : शबाना आजमी

नारी सशक्तिकरण पर आयोजित सेमिनार में महिलाओं ने रखे विचार

नई दिल्ली, एजेंसी। किसी भी समाज में नारी जितनी अधिक सशक्तहोगी वह समाज उतना ही अधिक सशक्त और संगठित होगा। यह बात पूर्व राज्य सभा सदस्य व अभिनेत्री शबाना आजमी ने रविवार को नारी सशक्तिकरण को लेकर ''अस्मिता' की ओर से आयोजित ''अस्मिता' एक वुमन लीडरशिप कांक्लेव' कार्यक्रम में कही।

कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एफ एमआरटी) की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो स्त्री को प्रकृति ने अधिक शक्तिशाली बनाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां पुरुष केवल अपने प्रोफेशनल जीवन मे तरक्की करके संतुष्ट हो जाते हैं वहीं महिलाएं अपने प्रोफेशनल दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्यों के निर्वाह भी लगातार करती रहती हैं। महिलाओं की प्राथमिकता जहां एक ओर उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है वहीं उनको अपने बच्चों के सम्पूर्ण विकास और उनके कैरियर के प्रति भी पूरी तरह से सजग और बच्चों के साथ लगातार संवाद भी करते रहना होता है। इस मौके पर कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोवना नारायण ने कहा कि यह आवश्यक है कि औरों से पहले आप स्वयं के प्रति सच्चे हों। स्वयं के प्रति सच्चा होना आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से हिचकिचाते नहीं है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो अपने प्रति सत्य होना ही हमें सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। ईटी नाऊ की न्यूज चीफ एडिटर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बोर्ड रूम तक जाना किसी कैट रेस की तरह नहीं है बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है अपने आप को पूरी तरह से परिष्कृत करने की। आईआईएम के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देबाशीश चटर्जी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण कोई एक दिन या कुछ दिन का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूत समाज के लिए नारी का सशक्तीकरण एक निर्बाध चलने वाली प्रक्रिया है। जी एंटर्टेमेंट की स्वतंत्र निदेशक निहारिका वोहरा, एसिड अटैक के खिलाफ आवाज उठाने वाली लक्ष्मी अग्रवाल और ट्रांसजेंडर समाज के अधिकारों के लिए लड़ रही कल्कि सुबरमानियम ने भी इस विषय में अपने विचार रखे। पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड शिवानी वजीर पसरीच ने अपने वक्तव्य में ''मैं' से ''हम' होने की प्रक्रिया को सशक्तिकरण का पहला कदम बताया।

क्रोध यमराज है -चाणक्य

हत्या का मुकदमा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार सवार को पुलिस द्वारा गोली मारने की घटना हमें एक साथ कई बातें सोचने को बाध्य करती है। गोली चलाने वाले सिपाही ने पहले कहा कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई और बाद में उसका बयान है कि रिवॉल्वर में गोली भरी होने के कारण चल गया वह चलाना नहीं चाहता था। इन दो प्रकार के बयानों का अर्थ ही है कि मामले में गड़बड़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने दोनों सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। किंतु पूरी घटना को समझने के बाद इस प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं मिलता कि आखिर सीधे फ्रंट से गाड़ी चला रहे एप्पल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली क्यों मारी गई? अगर पुलिस गाड़ी रोकना चाहती थी और वो नहीं रुके तो टायर में गोली मारी जा सकती थी, ट्रैफिक को त्वरित सूचना देकर बैरिकेडिंग लगवाई जा सकती थी..पीछा किया जा सकता था..। इससे प्रदेश की पुलिस पग्राली सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश से अपराधियों का नाश करने के लिए जिस पुलिस को मुठभेड़ की स्वायत्तता दी गई है, उसके सिपाही इतने गैर जिम्मेवार हों कि एक मनुष्य की जिंदगी की कीमत न समझें तो फिर यकीन करना मुश्किल है कि मुठभेड़ के नाम पर जितनी मौतें हुई हैं, सभी में कानून का पालन किया ही गया होगा। इन दो पुलिस वालों का पूरा व्यवहार पुलिस का कम अपराधी का ज्यादा लगता है। मिनट में बिना किसी कारण के एक निरपराध व्यक्ति का पूरा हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। जांच चाहे पुलिस करे या सीबीआई इससे परिवार की खुशियां वापस नहीं आ सकतीं। हालांकि मृतक के परिवार, दोस्तों एवं आम जनता के तेवर को देखते हुए मुआवजे से लेकर एक नौकरी तक का वायदा आदित्यनाथ योगी सरकार ने कर दिया है। यह आवश्यक भी था, क्योंकि पुलिस अगर हत्या करे तो उस परिवार के भरण-पोषण का दायित्व सरकार को लेना ही चाहिए। इस भयावह घटना से सबक लेकर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिले-जिले में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके पुलिसकर्मियों को बताए कि कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए कैसे निपटा जा सकता है? साथ ही सभी पुलिसवालों का रिकॉर्ड खंगाला जाए जिससे संदिग्धों की छंटनी हो सके। उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों पर राजनीतिक नजरिए से पुलिस भर्ती का आरोप लगा था, जिसमें काफी सच्चाई थी। इसलिए प्रदेश की पुलिस की सफाई आवश्यक है।

''आतंकी रक्तपात'

देश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा के वार्षिक अधिवेशन में एक साथ भारत की विकास नीति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेवारी, विश्वदृष्टि, वैदेशिक संबंधों, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष..आदि के बीच संतुलन बताते हुए जिस तरह अपनी बात रखी वह हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। उन्होंने भाषण के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति कभी भी एक राष्ट्र के रूप में हमें संकुचित नहीं बनाता। हम वसुधैव कुटुम्बकम के आचारण वाले देश हैं, जिसका अर्थ है कि सम्पूर्ण वसुधा पर बसने वाले हमारे परिवार के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन ऐसा अवसर होता है, जब दुनिया के देश अपने साथी देश को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत को उसके उदार चरित्र के रूप में पेश किया जाना आवश्यक होता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि जो तात्कालिक सवाल हमारे व्यवहार के संदर्भ में उठते हैं, उनका उत्तर नहीं दिया जाता। सुषमा ने पाकिस्तान से रिश्ता एवं वार्ता प्रक्रिया पर भारत का मत स्पष्ट करते हुए साफकर दिया कि जब तक आतंकवाद पर सकारात्मक रवैया नहीं दिखेगा बातचीत का आधार बन ही नहीं सकता। उन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ को भी अनावृत्त कर दिया कि भारत वार्ता प्रक्रिया को बाधित करता है। यह सवाल करके कि हत्यारों को महिमामंडित करने वाले देश के साथ ''आतंकी रक्तपात' के बीच कैसे वार्ता की जा सकती है; सुषमा ने विश्व नेताओं को ही सोचने को विवश किया कि आप हमारी जगह होते तो क्या करते? 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के मुख्य खलनायक ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान से मिलने की चर्चा करके उन्होंने पाकिस्तान के चरित्र को नंगा करने की रणनीति अपनाई, जो विश्व मंचों पर बात तो आतंकवाद के विरोध की करता है लेकिन व्यवहार में आतंकवादियों को अपने यहां पालता-पोसता है। भारत की नीति ही है कि बातचीत जटिल विवादों को हल करने का एकमात्र तर्कसंगत माध्यम है। किंतु एक ओर बातचीत का आग्रह और दूसरी ओर भारतीय जवानों का अपहरण कर उनकी बेरहमी से हत्या संबंध सुधारने का व्यवहार तो नहीं हो सकता। सुषमा के संयत और तार्किक भाषण से दुनिया को संदेश मिल गया होगा कि वार्ता और सामान्य संबंध के आड़े पाकिस्तान की आतंकवाद प्रायोजित करने की नीति है।

संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन

व्यभिचार अनहैप्पी मैरिज यानी अप्रसन्न विवाह का केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे अपराध मानकर केस करेंगे, तो इसका मतलब दुखी लोगों को सजा देना होगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कानून मनमाना है, महिला की सेक्सुअल च्वॉइस को यानी उसे यौन विकल्प अपनाने से रोकता है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ की महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने कहा कि कोई ऐसा कानून जो पत्नी को कमतर आंके, ऐसा भेदभाव संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक महिला को समाज की मर्जी के मुताबिक सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन न्यायाधीशों ने यूं ही यह निष्कर्ष भी नहीं दिया है। इसमें अलग-अलग देशों के कानूनों, प्राचीन से लेकर आधुनिक धर्मग्रंथों, संहिताओं आदि को उद्धृत किया गया है। अंग्रेजों के समय भी लॉड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता के पहले दस्तावेज में व्यभिचार को एक दंडनीय अपराध बनाने से इनकार कर दिया था।

सतीश पेडणोकर

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले दिए हैं, जिन पर सघन बहस चल रही है। विवाहेतर यौन संबंधों यानी व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का मामला ऐसा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया और कहा कि यह महिलाओं की स्वायत्तता और व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यहां तक कह दिया कि इस प्रावधान ने महिलाओं को पतियों की संपत्ति बना दिया था। किंतु महिलाओं के साथ समानता के अधिकार का समर्थन करने और व्यवहार में उसे जीने वालों ने भी इस फैसले पर चिंता प्रकट की है। चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय का है इसलिए कोई बड़ा व्यक्तित्व सीधे विरोध में नहीं उतरा है, लेकिन वातावरण वैसा ही है, जैसे समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने के फैसले के समय था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।

महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता। संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें ''मैं, मेरा और तुम' सभी शामिल हैं। पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति एएम खानिवलकर ने कहा कि ये पूरी तरह से निजता का मामला है। व्यभिचार अनहैप्पी मैरिज यानी अप्रसन्न विवाह का केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे अपराध मानकर केस करेंगे, तो इसका मतलब दुखी लोगों को सजा देना होगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कानून मनमाना है, महिला की सेक्सुअल च्वॉइस को यानी उसे यौन विकल्प अपनाने से रोकता है।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा कि यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ की महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ने कहा कि कोई ऐसा कानून जो पत्नी को कमतर आंके, ऐसा भेदभाव संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एक महिला को समाज की मर्जी के मुताबिक सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन न्यायाधीशों ने यूं ही यह निष्कर्ष भी नहीं दिया है। इसमें अलग-अलग देशों के कानूनों, प्राचीन से लेकर आधुनिक धर्मग्रंथों, संहिताओं आदि को उद्धृत किया गया है। अंग्रेजों के समय भी लॉड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता के पहले दस्तावेज में व्यभिचार को एक दंडनीय अपराध बनाने से इनकार कर दिया था। जिस पृष्ठभूमि में इस कानून को लागू किया गया उसे भी साफ किया है। 1860 में जब भारतीय दंड संहिता लागू हुई तो एक बड़ी आबादी खासकर हिन्दुओं में तलाक को लेकर कोई कानून नहीं था क्योंकि शादी को एक संस्कार माना जाता था। 1955 तक हिन्दू पुरुष को कई महिलाओं से शादी करने की आजादी थी। उस समय व्यभिचार तलाक का आधार नहीं हो सकता था, क्योंकि तलाक के कानून ही नहीं थे। हालांकि सच यही है कि हिन्दू समाज में पुरुषों का बहुविवाह कभी भी आम प्रचलन नहीं रहा। वैसे इस पुराने कानून के दो मुख्य आधार खत्म हो चुके हैं। 1955-56 के बाद हिन्दू कोड लागू हो गया, जिसके तहत हिन्दू पुरुष केवल एक ही औरत से शादी कर सकता है। हिन्दुओं के लिए भी तलाक का कानून बन गया और व्यभिचार को हिन्दू कानूनों में तलाक का आधार भी बना दिया गया। अब यहां इस कानून को समझना जरूरी है। धारा-497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो केवल उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती थी। धारा 497 केवल उस पुरुष को अपराधी मानती थी, जिसके किसी और की पत्नी के साथ संबंध हों। निष्कर्ष यह निकाला गया कि महिला के पति को ही शिकायत का हक होना कहीं-न-कहीं महिला को पति की संपत्ति जैसा दर्शाता है। किंतु इसमें अगर पत्नी को मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं था तो उसे विवाहेतर यौन संबंधों पर आपराधिक मामला का सामना करने से ही वंचित रखा गया। इस नाते इसे केवल महिलाओं के खिलाफ मानना शत-प्रतिशत सही नहीं लगता। दूसरे, अगर अपराध नहीं माना जाएगा तो पति अपनी महिला दोस्त के साथ पत्नी की जानकारी में भी संबंध बनाए तो वह उस महिला के पति के माध्यम से भी मामला दर्ज नहीं करा सकती। और तलाक? तो जो पुरुष ऐसा करेगा वह तो शायद पत्नी से पिंड छुड़ाने की तैयारी कर चुका होगा। तो समस्या महिला के साथ भी खड़ी होगी। ध्यान रखिए, इस मामले के याचिकाकर्ता केरल के अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने धारा-497 को चुनौती देते हुए कहा था कि कानून लैंगिक दृष्टि से तटस्थ होता है लेकिन इसके प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है। इसे लैंगिक तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) करने का संविधान पीठ से अनुरोध किया गया था। यानी विवाहेतर संबंध वाले महिला और पुरुष दोनों को अपराध की परिधि में लाया जा सके। कानून को रद्द करने का संदेश यह जा रहा है कि अब विवाहेतर यौन संबंधों को पूरी आजादी मिल गई है। भारत में विवाह आज भी एक संस्कार है। इसमें यौन नैतिकता सवरेपरि है। यदि यह स्तंभ टूट गया तो केवल यौन स्वैच्छाचार को ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, परिवार का विघटन होने लगेगा। हालांकि फैसले में ही कुछ बातें कही गई हैं। जैसे यह तलाक का आधार तो बन सकता है लेकिन अपराध नहीं। अगर इस वजह से पार्टनर खुदकुशी कर ले खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है। कोई व्यवहार शादी टूटने का आधार बन सकता है, आत्महत्या का कारण बन सकता है लेकिन उस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इस व्यवस्था पर पुनर्विचार जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि विवाहेतर संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के वर्तमान और समलैंगिकता को भी मान्य कर देने के फैसले के विरुद्ध अलग-अलग पुनर्विचार याचिकाएं डाली जाएं। फैसले में दीपक मिश्रा ने कहा कि हम मानते हैं कि यहां आपसी रिश्ते कानून से नहीं भावनाओं और सदियों से चली आ रही सामाजिक दायित्व बोध से कायम रहते हैं। किंतु कानून से इन सबको मुक्त करने का भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा और वह नकारात्मक ही होगा।

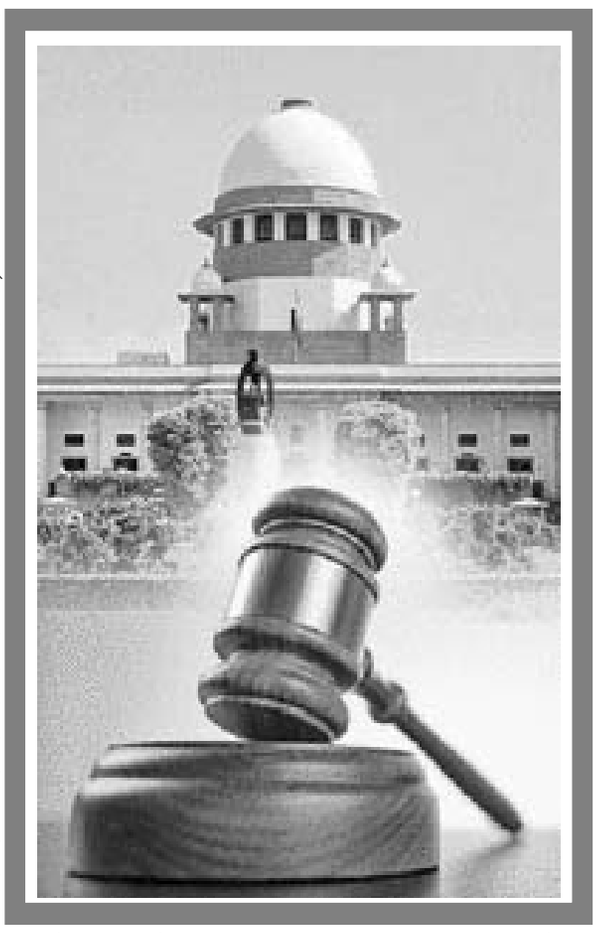

चलते चलते

''एग्जाम वॉरियर'

बोर्ड से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद छात्रों की आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। साथ में होते हैं उनके दिल बैठा देने वाले सुसाइड नोट।

परीक्षा और उसके परिणाम का दबाव कई विद्यार्थियों के जीवन को असमय लील जाता है। बोर्ड से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद छात्रों की आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। साथ में होते हैं उनके दिल बैठा देने वाले सुसाइड नोट। जिनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने परीक्षा को ही जिंदगी मान ली थी। आसपास के परिवेश और अभिभावकों का अपने बच्चों पर सफलता का भारी दबाव भी अनहोनी का माहौल रचता है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहीं शिल्पा ठाकुर भी परीक्षा में असफलता का दबाव नहीं झेल पाई, और मौत को गले लगा लिया। वो तीन बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुकीं थीं। शिल्पा के सुसाइड नोट से तनाव और उसके अकेलापन का पता चलता है।2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर चार घंटे में एक छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। यह वैश्विक रूप से सबसे उच्चतम दरों में से एक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)के अनुसार 2015 में 8,934 छात्रों ने आत्महत्या की थी। यह संख्या साल दर साल कम नहीं है। बोर्ड परीक्षा पास होने की अनिवार्यता खत्म करने से लेकर स्कूलों में कॉउंसलिंग तक के प्रयोग अपनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा के दबाव से निपटने के लिए ''एग्जाम वॉरियर' नाम की किताब भी लिखी है। मगर तमाम तरह के विचार, समझाइश और प्रयोग परीक्षा के दबाव को सिर्फ काउंटर करने तक ही सीमित हैं। आत्महत्या का सीधा संबंध मानसिक मजबूती और दबाव झेलने से है। और इसी मोर्चे पर छात्र कमजोर पड़ जाते हैं। हथियार डाल देते हैं। मानसिक मजबूती और असफलता का दबाव झेलने की ताकत; कोई शार्ट टर्म कोर्स नहीं है। यह प्रक्रिया घर की परवरिश से लेकर स्कूल-कॉलेज तक चलनी चाहिए। इसके लिए बकायदा पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। जो छात्रों के नैसर्गिक विकास में भागीदार बने। किसी छात्र की आत्महत्या सिर्फ उस अकेले छात्र की असफलता नहीं है, बल्कि उस परवारिश और उस शिक्षा व्यवस्था की भी घोर असफलता है, जो उसे असफलता से आंखें मिला पाने का मजबूत दिल और दिमाग भी नहीं दे पाती। उसे इतना भर नहीं बता पाती कि असफलता ही सफलता का दरवाजा खोलती है। लिहाजा हमें बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा। यही एकमात्र हल है।

इच्छा मृत्यु की मांग

ठाकुरद्वार में रहने वाले वयोवृद्ध बेऔलाद दंपति नारायण लावते (88) और उनकी पत्नी इरावती (78) ने पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। वजह उन्हें लगता है कि समाज के लिए या खुद अपने लिए अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। वे अपनी देखभाल भी खुद नहीं रख सकते। दंपति ने अपनी याचिका में अपना बचा हुआ धन राज्य के कोषागार में जमा कराने का वादा भी किया है। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी गंभीर रोग से उनके ग्रसित होने तक उन्हें मृत्यु का इंतजार करने के लिए मजबूर करना अनुचित है। बता दें कि इरावती स्कूल प्रिंसिपल रह चुकी हैं, जबकि नारायण पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। इसी तरह बरेली में रहने वाली मेरी दूर की एक रिश्तेदार 68 साल की मालती का भी जीवन से मोहभंग हो चुका है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं; लेकिन बुढ़ापे में अपनों ने जो दर्द दिया, उसे वह ताउम्र नहीं भूल सकतीं। उनके पति अच्छी सरकारी नौकरी में थे। दस साल पहले रिटायर होने के बाद पीएफकी रकम से उन्होंने एक मकान बनवाया ताकि जिंदगी की दूसरी पारी अपने घर में सुकून से बीत सके। अपने दोनों बेटों को कारोबार के लिए भी पैसे दिए और बेटी की अच्छी शादी भी की लेकिन चार साल पहले पति का निधन होते ही बेटों-बहुओं की नजरें बदलने लगीं। बेटों ने बहला-फुसला कर न सिर्फमकान अपने नाम लिखवा लिया वरन जमा पूंजी भी हथिया ली। यही नहीं, उनके खाने-पीने और जरूरी खर्चों में भी कटौती की जाने लगी। धीरे-धीरे जब अपनों के अत्याचार सहन सीमा से बाहर हो गए तो मालती ने खुद ही अपने पति की गाढ़ी कमाई से बनवाया घर छोड़ दिया। इस उम्र में वह साग-सब्जी बेच कर गुजारा करती हैं। वह कहती हैं, ''इस जिंदगी में मेहनत तो है लेकिन सुबह-शाम चैन से दो रोटी तो खा लेती हूं।' मालती और मनोहर जैसे बुजुगरे की ऐसी दर्द भरी कहानियां देश के हर छोटे-बड़े शहर में आम हैं। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी काबिलेगौर है। 70 वर्षीय किराना व्यवसायी मोतीलाल गुप्ता के मुताबिक बुढ़ापे को अपने पर हावी नहीं होने देना व्यक्ति की सोच और जीवनशैली पर निर्भर करता है। वह कहते हैं कि मैं पिछले 35 वर्षों से रोजाना सुबह की सैर के बाद अपनी दुकान पर पहुंच कर सारे कामकाज संभाल रहा हूं। आज भी यह जारी है। बेशक मेरा बेटा दुकान ठीक प्रकार से संभाल लेता है, लेकिन रोजाना दुकान पर बैठना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह बुजुर्ग छोटेलाल वर्मा कहते हैं कि उम्र के अनुसार शरीर अपने आप ढल जाता है। इस उम्र में मेरी बोलने और सुनने की क्षमता में जरूर कमी आई है, लेकिन उम्र का असर मेरी कार्यक्षमता पर नहीं पड़ा। मैं पिछले 32 साल से टेन्ट हाउस संचालित कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनपीएफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2050 तक भारत में बुजुगरे की तादाद बढ़ कर तीन गुनी हो जाएगी। आज देश में जीवन प्रत्याशा औसतन 68 वर्ष से अधिक हो गई है। ऐसे में इस मुद्दे पर गहराई से चिंतन की जरूरत है। यूएनपीएफका कहना का कि वर्ष 2050 तक देश में बुजुगरे की आबादी बढ़ कर 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में उनकी सुरक्षा व देखरेख के लिए ठोस कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। बुजुगरे में खासकर महिलाओं पर खास ध्यान देना जरूरी है क्योंकि पुरुषों के मुकाबले उम्र लंबी होने और ज्यादातर मामलों में कोई आय नहीं होने या मामूली आय होने की वजह से बुढ़ापे में उनकी स्थिति

सत्संग

चेतना को विकसित

नवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो, तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिधि है। उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवन-यापन को भी सब कुछ न मानकर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी, जो इस ब्रह्मण्ड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेने वालों पर अपनी उच्चस्तरीय अनुकंपा बरसाती है। साथ ही मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्त्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिसे थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है। इस अध्यात्म विकास के तत्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वार मनुष्य शरीर मिलने के बाद खुलता है।

इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है। यह दूसरी बात है कि वह उस अनुदान का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ किन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करता है। विकास की मानवीय परत में उभरते ही उसे आत्मबोध की एक नई उपलब्धि हस्तगत होती है वह अनुभव करता है कि काय-कलेवर उसका समग्र स्वरूप नहीं वरन एक वाहन उपकरण आच्छादन मात्र है। उसके भीतर रहने वाली चेतना ही मनुष्य को ऊंचा उठाती, नीचे गिराती है। मन:स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता आप है। वह प्रकृति की कठपुतली मात्र नहीं है। व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सज्जा को, अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुत: मनुष्य नर-पशु ही रहता है और इंद्रिय लिप्साओं और मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्त्व समझ पाता है और न उसे चेतना की पृथकता, विशिष्टता संबंधी कुछ ज्ञान होता है।

फोटोग्राफी...

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में केलोंग के बारा-लाचा मार्ग पर भारी हिमपात के कारण यातायात ठप हो गया।

जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि, सितंबर में बढ़कर 94,442 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। जीएसटी संग्रह सितंबर में बढ़कर 94,442 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले महीने में यह 93,690 करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह कहा। मंत्रालय के अनुसार सितंबर महीने में 67 लाख माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल किए गए। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 15,318 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 21,061 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 50,070 करोड़ रुपए (आयात से 25,308 करोड़ रुपए का संग्रह शामिल) तथा उपकर 7,993 करोड़ रुपए रहा है। उपकर में 769 करोड़ रुपए आयात पर किया गया संग्रह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, ''केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कुल राजस्व सितंबर 2018 में सीजीएसटी 30,574 करोड़ रुपए तथा एसजीएसटी 35,015 करोड़ रुपए रहा है।''

नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, जब्त की 637 करोड़ की संपत्ति

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी कांड में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने नीरव मोदी और उसके परिवार की भारत एवं चार अन्य देशों में 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। के तहत ईडी ने न्यूयॉर्क में नीरव की 216 करोड़ रुपए मूल्य की 2 अचल संपत्ति जब्त की है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में किसी आरोपी की संपत्तियां जब्त की हैं। वहीं, इस मामले में ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी पांच विभिन्न आदेशों के तहत जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी पीएमबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल, नीरव और चोकसी दोनों ही देश से फरार हैं।

वोटर आईडी से जोड़ा जाएगा आधार, आयोग ने शुरू की तैयारी

नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया आदेश के अनुरूप दोबारा शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के सचिवालय को आधार और चुनावी राजनीति को अपराधमुक्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। आधार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध करार देने के बाद वोटर आईडी से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा- 'यह परियोजना, अदालत में आधार का मामला विचाराधीन होने के कारण रोकनी पड़ी थी। अब फैसले के अध्ययन के बाद अदालत के आदेश के अनुरूप इसे फिर से शुरू किया जा सकेगा।' रावत ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए फरवरी 2015 में आधार से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की योजना शुरू की गई। अगस्त 2015 में आधार की वैधता से जुडा मामला सर्वोच्च अदालत पहुंच गया। तब तक लगभग 33 करोड़ मतदाता पहचान पत्र आधार से जोड़े जा चुके थे। इसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने के सवाल पर उन्होंने कहा योजना को शुरू करने भर की देर है। काम को यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश होगी। देखते हैं कि कितना समय लगता है। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के संबंध में रावत ने कहा कि आयोग इस फैसले का भी अध्ययन कर इसे यथाशीघ्र लागू करने के उपाय करेगा। न्यायालय ने अपने फैसले में उम्मीदवारों को उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचाने को कहा था।

लगातार तीसरे महीने घटी मारुति की बिक्री

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की यात्री कारों की बिक्री में सितम्बर में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गयी। साथ ही निर्यात समेत कंपनी की कुल बिक्री भी लगातार तीसरे महीने घटी है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि छोटी कारों की बिक्री घटने से सितम्बर में उसकी यात्री कारों की बिक्री 1.4 प्रतिशत घटकर 1,15,228 इकाई रह गयी। पिछले साल सितम्बर में यह 1,16,886 इकाई रही थी। छोटी कारों की बिक्री 9.1 प्रतिशत कम होकर 34,971 इकाई रह गयी। वहीं, कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री 1.7 प्रतिशत बढ़कर 74,011 पर और मिडसाइज कारों की 11.5 प्रतिशत बढ़कर 6,246 पर पहुँच गई। यात्री वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,51,512 इकाई रही। यात्री वाहनों में कारों के साथ उपयोगी वाहन और वैन आते हैं। इनमें उपयोगी वाहनों की बिक्री 8.7 प्रतिशत बढ़कर 21,639 पर और वैनों की 6.6 प्रतिशत बढ़कर 14,645 पर पहुँच गई।

बढ़ रही है रिटर्न नहीं फाइल करने वालों की संख्याो

नई दिल्ली।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत करदाताओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन साथ ही रिटर्न नहीं फाइल करने वाले करदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल 01 जुलाई से देश भर में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी लागू की गई थी। उस समय पंजीकृत करदाताओं की संख्या 74,61,214 थी। सूत्रों ने बताया कि अब तक 87.02 प्रतिशत ने जुलाई 2017 के लिए रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं, इस साल जुलाई में पंजीकृत करदाताओं की संख्या बढ़कर 94,70,282 पर पहुंच गई है लेकिन इनमें से 73.15 प्रतिशत ने ही रिटर्न दाखिल किया है। जीएसटी के तहत डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले करदाताओं को अब तिमाही रिटर्न भरना होता है जिसकी अंतिम तिथि तिमाही समाप्त होने के बाद एक महीने तक होती है। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वालों को हर महीने रिटर्न दाखिल करना होता है और इसके लिए उन्हें 20 दिन का समय मिलता है। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल करने में जुर्माना देना होता है। हालांकि जीएसटी परिषद् समय-समय पर विभिन्न कारणों से अंतिम तिथि जुर्माने में राहत देती रही है। सूत्रों ने बताया कि चिंता की बात यह है कि रिटर्न नहीं भरने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2017 के लिए उस समय पंजीकृत 88.60 प्रतिशत करदाताओं ने अब तक रिटर्न दाखिल किया है। दिसंबर 2017 के लिए 87 प्रतिशत, इस साल जनवरी के लिए 86 प्रतिशत, फरवरी के लिए 85 प्रतिशत और मार्च के लिए 83 प्रतिशत करदाताओं ने रिटर्न भरा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल के लिए 82 प्रतिशत, मई के लिए 79 प्रतिशत, जून के लिए 77 प्रतिशत और जुलाई के लिए 73.15 प्रतिशत रिटर्न अब तक भरा गया है। सबसे ज्यादा 93.28 प्रतिशत रिटर्न पिछले साल अगस्त के लिए भरे गए हैं। उनका कहना है कि जुलाई के लिए कंपोजिट श्रेणी के डेढ़ करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करदाताओं के रिटर्न 31 अक्टूबर तक भरे जाने हैं इसलिए इस आँकड़े में सुधार की

गुंजाइश है लेकिन, पुराने आंकड़ों में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। वहीं, एक सकारात्मक सुधार यह हुआ है कि रिटर्न भरने वालों में बड़ी संख्या में लोग अब समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने लगे हैं।

ताकि उन्हें जुर्माना न देना पड़े। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह बताया था।

महंगाई की चौतरफा मारः पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि,

बिजनेस डेस्क।

तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच 1 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में जहां पेट्रोल की कीमत में 0.24 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल की कीमत में 0.30 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में, रविवार तक 83.49 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलने वाला पेट्रोल अब 83.73 रुपए प्रति लीटर के दर पर मिलने लगा है। दूसरी तरफ, 74.79 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा डीजल अब 75.09 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिकने लगा है। मुंबई में सोमवार को पेट्रोल में 0.24 पैसे और डीजल में 0.32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। अब मुंबई में पेट्रोल 91.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.72 रुपए प्रति लीटर की दर पर मिलने लगा है। केवल इतना ही नहीं, आपको सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस (पीएनजी) का उपयोग करने के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में अब सीएनजी 1 रुपया 70 पैसा महंगा हो गया है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसमें 1 रुपया 95 पैसा की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह, रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी के दाम में भी वृद्धि की गई है। दिल्ली में पीएनजी की कीमत में 1.30 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की बढ़ोत्तरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने रविवार की आधी रात से कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा, बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सोमवार से 59 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वहीं, सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी 2.89 रुपए की वृद्धि की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक, रुपए में हो रहे उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के चलते अब दिल्ली में सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 502.4 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा सब्सिडी वाली घरेलू गैस की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी 2.89 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। यह इजाफा जीएसटी के कारण हुआ है।

देश में हो सकती है दवाओं की किल्लत

नेशनल डेस्क। भारत 60 फीसदी बल्क दवा चीन से आयात करता है। चीन ने अब इसका निर्यात धीरे-धीरे घटाना शुरू कर दिया है, जिससे देश में दवाओं की किल्लत हो सकती है। देश के मेडिकल स्टोर्स पर विटामिन-सी की दवाओं को छोड़कर फिलहाल अन्य दवाओं की कमी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड और अन्य दवाओं का मिलना मुश्किल हो सकता है। चीन की कंपनियां अपने संयंत्रों को अपडेट कर रही हैं, इससे दवाओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कुछ दवाओं का उत्पादन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी बंद किया जा रहा है। वहीं, बल्क दवाओं को बनाने वाली सामग्री (एपीआई) भारत में उपलब्ध न होने के कारण भी इनकी बिक्री में गिरावट आई है। मेडिकल उद्योग के जानकारों का कहना है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो देश में दवाओं में कमी आ सकती है और यह परेशानी का सबब बन सकता है। मेडिकल उद्योग से संबंधित कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बल्क दवाओं का स्टॉक भी खत्म हो रहा है और इसकी बिक्री शायद जल्द ही बंद करनी पड़े। भारतीय दवा निर्माता कंपनियों के संगठन आईडीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपनाथ राय चौधरी ने कहा कि इस संबध में सरकार को जानकारी दे दी गई है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल है।

हवाई सफर होगा महंगा, मोदी राज में एटीएफ की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली।

जल्द ही हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। मोदी सरकार के राज में हवाई ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने एक अक्टूबर से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी की है। दिल्ली में एटीएफ की कीमत 5,106 रुपए की बढ़त के साथ 74,567 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे पहले मार्च 2014 में इस की कीमत 74,825 रुपए प्रति किलोलीटर दर्ज की गई थी। वहीं, पिछले महीने (सितंबर) में दिल्ली में एटीएफ की कीमत 69,461 रुपए प्रति किलोलीटर दर्ज की गई। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के साथ कंपनियों के मुनाफे पर भी असर होगा।

ऐसे में, किराए में बढ़ोत्तरी होना लाजमी है। हवाई सफर महंगा होने से सब से बड़ा झटका उन यात्रियों को लगेगा जो त्योहारों में सफर करते हैं। इन दिनों लोग बड़ी संख्या में सफर करते हैं। पिछले साल अक्टूबर से अब तक हवाई ईंधन 21 हजार, 500 रुपए यानी 40 फीसदी महंगा हो चुका है। अक्टूबर 2017 में एटीएफ की कीमत 53,045 रुपए प्रति किलोलीटर थी, जो पहली अक्टूबर 2018 में बढ़कर 74,567 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गई है।

बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 59 रुपए, सब्सिडी वाला 2.89 रुपए महंगा

नई दिल्ली।

सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2.89 रुपए बढ़कर 502.4 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अक्टूबर में 59 रुपए महंगा हो गया। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोत्तरी प्रमुख तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढने और विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के चलते की गई है। कंपनी ने बताया कि सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत पर वास्तिवक प्रभाव मात्र

2.89 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ेगा। इसकी प्रमुख वजह उस पर जीएसटी का लगना है।

अक्टूबर में ग्राहकों के खाते में 376.60 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी जमा की जाएगी जो सितंबर 2018 में 320.49 रुपए थी।

गैस आधारित बिजली संयंत्रों की ओएनजीसी से अधिक गैस आवंटन की मांग

हैदराबाद। गैस आधारित बिजली संयंत्रों ने ओएनजीसी के गहरे समुद्र के गैस कुंओं से अधिक गैस आवंटन की मांग की है क्यों की गैस की कमी के कारण ऐसे बिजली संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता का इस्तेमाल (प्लांट लोड फैक्टर - पीएलएफ) ऊंचा नहीं रख पा रहे हैं। बिजली उत्पादकों के संघ (एपीपी) ने इस संबंध में 28 सितंबर को विद्युत मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। पत्र में एपीपी ने कहा कि भारत में गैस आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापित उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट है। लेकिन घरेलू स्रोतों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन कम होने या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों की गैस की कीमतें बहुत ऊंची होने से इनका परिचालन आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त स्तर तक नहीं हो पा रहा है। पिछले सात सालों में गैस आधारित संयंत्रों का पीएलएफ 43 प्रतिशत नीचे आया है। वित्त वर्ष 2010 - 11 में यह 66 प्रतिशत था जो 2017 - 18 में गिर कर 23 प्रतिशत रह गया। एपीपी का कहना है कि ओएनजीसी का गहरे पानी के गैस कुंए से उत्पादन बढ़ा है और उसी मात्रा में बिजली संयंत्रों को भी आवंटित किया जा सकता है। इससे पुनर्गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की हिस्सेदारी घटेगी और बिजली की दरें भी प्रतिस्पर्धी बनेंगी।

एसबीआई यूजर्स अब एसबीआई से नहीं निकाल पाएंगे ज्यादा कैश

नई दिल्ली।

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंट (एसबीआई) ने दिवाली से पहले एटीएम से कैश निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। एसबीआई ने कैश निकालने की दैनिक सीमा में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर से ग्राहक एक दिन में अधिकतम 20 हजार रुपए कैश ही एटीएम से निकाल सकेंगे। अभी तक यह सीमा 40 हजार रुपए थी। एसबीआई के बाद देश के बाकी बैंक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। ने ब्रांचों को भेजे आदेश में कहा है कि एटीएम ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए और डिजिटल-कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैश निकासी सीमा को घटाने का फैसला किया गया है। कैश निकासी सीमा में कटौती फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले हुई है। सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर दिए जाने के बावजूद कैश की डिमांड अधिक बनी हुई है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, बाजार में कैश फ्लो नोटबंदी से पहले के स्तर तक पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में पाया गया है कि कार्ड का क्लोन बनाने वाले धोखेबाज आम बैंक कस्टमर्स के डेबिट कार्ड का ब्यौरा चोरी से लगाए गए कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पता कर लेते हैं। कुछ बड़े बैंकों की क्रेडिट कार्ड ग्रोथ को छोटे शहर बढ़ावा दे रहे हैं और टॉप 10 शहरों के बाहर के कार्ड होल्डर्स इस तरीके से होने वाले खर्च में 40-45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। बैंकिंग कोड एडं स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की मुताबिक अगर बैंक नए नियम लागू करता है, तो उसे कम से कम

30 दिन पहले कस्टमर को सूचित करना होगा। ऐसे में, एसबीआई की ओर से कस्टमर को नए नियम के बारे में सूचित करने के लिए सभी ब्रांचों को एक नोटिस जारी किया गया है।

सेवा क्षेत्र में खुलापन वृद्धि में मददगार

वाशिंगटन।

भारत के आर्थिक सुधार और वृद्धि की कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि सेवा क्षेत्र से जुड़ी उदार नीति लंबे समय में वृद्धि में सहायक होती है और विनिर्माण क्षेत्र की भी उत्पादकता बढती है। आईएमएफ, विश्वबैंक और डब्ल्यूटीओ की एक संयुक्त ताजा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक में भारत में किए गए सुधार से अधिक खुलापन, बेहतर नियमन और अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसकी बदौलत भारतीय विनिर्माण इकाइयों के पास घरेलू एवं विदेशी सेवा प्रदाताओं से सेवा लेने के विकल्प बढ़ गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्वबैंक और विश्व व्यापार संगठन की ओर से जारी रिइनविगोरेटिंग ट्रेड एंड इन्क्लुसिव ग्रोथ (व्यापार और समावेशी वृद्धि को सशक्त बनाना) शीर्षक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माताओं को बेहतर, अधिक विश्वसनीय और अधिक विविधतापूर्ण व्यापार सेवाओं का विकल्प मिला है। इससे उन्हें नए - नए कारोबार और प्रौद्योगिकी में निवेश के अवसर मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से इकाइयों को अपेक्षाकृत कुछ ही जगह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने, स्टॉक के कुशल प्रबंधन और आपूर्तिकर्ता एवं ग्राहकों के साथ समन्वय कर निर्णय करने का अवसर मिलता है। वर्ष 2016 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बैंकिग, बीमा, दूरसंचार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधारों से विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी और स्थानीय दोनों तरह की कंपनियों की उत्पादकता बढ़ी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस बात को पूरी तरह से स्थापित करता है कि सेवा क्षेत्र को उदार बनाए जाने से लंबी अवधि की वृद्धि हासिल करने में मदद मिलती है।

मंडियों में पहुंचने लगा है किसानों का सोना शुरू हुई धान और बाजरे की सरकारी खरीद

चंडीगढ़।

प्रदेश में धान और बाजरे की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है. किसानों के धान और बाजरे की फसल की खरीद के लिए सरकार की तरफ से मंडियों और सरकारी खरीद एजेंसियां निर्धारित कर दी गई हैं। बता दें बाजरा उन किसानों का ही खरीदा जाएगा जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जबकि धान की खरीद ओपन रहेगी। बाजरे की खरीद के लिए हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन तीनों अनाज मंडियों में तीन-तीन दिन खरीद करेंगी और धान की खरीद केवल एफसीआई की तरफ से की जाएगी। जबकि क्षेत्र में धान की खरीद सरकारी ही नहीं प्राईवेट मिलों के लिए भी की जाएगी, क्योंकि धान की जिन किस्मों की खरीद सरकार की तरफ से की जाती है उस धान की खेती काफी कम क्षेत्र में की जाती है। सरकार ने इस बार बाजरा की खरीद को लेकर कोई घालमेल न हो इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है। जिसके तहत प्रदेश में 1 लाख 36 हजार 208 किसानों ने पोर्टल पर अपना ब्योरा दर्ज कराया है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिन किसानों ने पोर्टल पर अपना ब्योरा दिया है और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन किसानों का ही बाजरा खरीदा

जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बार किसानों का बाजरा खरीदने के लिए 1950 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया हुआ है।

सैयदपुरा में शेख परिवार को सूदखोरों ने दी जान से मारने की धमकी

सूरत। सैयदपुरा इलाके में शेख परिवार 18 लाख की वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवायी गई है।

लालगेट पुलिस सूत्रों अनुसार सैयदपुरा मसेमन एपार्टमेन्ट निवासी साकेराबीबी अकील शकील शेख शुक्रवार रात दस बजे घर पर थी तभी फायनान्सर सिद्दीक वाजा अपने चार साथियों के साथ घर आया था और साकेराबीबी को अपने पति को ब्याज पर लिए 18 लाख रूपए चुकाने का कहकर रूपए नहीं चुकाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने साकेराबीबी की तहरीर्र के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

कतारगाम में अधेड़ ने की बालिका के छेड़खानी

सूरत। शहर के कतारगाम इलाके में आठ वर्षीय की बच्ची के साथ पड़ोसी ने शारीरिक छेड़खानी किए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवायी गई है। कतारगाम पुलिस सूत्रों के अनुसार कतारगाम खरी मोहल्ला निवासी किशन कैलाश त्रिपाठी (उम्र 50) ने गत रोज देर शाम साढे सात बजे आठ वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी उसका हाथ खिंचकर अंधेरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ किया। पुलिस ने किशन त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

मतदाता सूची में करवाया सुधार

अग्रवाल विकास ट्रस्ट का वोट करेगा युवा अभियान

सूरत। अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा द्वारा वोट करेगा युवा अभियान के अन्तर्गत युवा शाखा सदस्यों द्वारा एस.एम.सी 160 म. विद्याल सिटी लाईट में रविवार को लगाये गये कैम्प में मतदाता सूची में सुधार एवं नये मतदाताओं का नाम जुड़वाया गया। युवा शाखा के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल एवं प्रेरण दाता संजय सरावगी ने बताया की इस वर्ष लोकसभा चुनाव में युवा शाखा द्वारा भारत के सौ से ज्यादा शहरों में वोट करगा युवा अभियान चुनाव आयोग के साथ मिलकर चलाया जायेगा।

फोगवा और किसानों की विविध मांगों को लेकर रैली निकली

सूरत। क्रेडिट लेप्स और स्थानीय समस्याओं को लेकर फोगवा द्वारा घन कचरे के समाधान के लिए प्रोजेक्ट के विषय पर सोमवार को भांडुद गांव के किसान द्वारा पैदल रैली निकालकर पालिका कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। फोगवा द्वारा इससे पहले की गई घोषणा के अनुसार स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार सुबह उधना सोनल इण्डस्ट्रीयल के पास से पैदल रैली निकाली गई। जिसमें क्रेडिट लेप्स का समाधान नहीं आने से बैनर्स लेकर केन्द्र सरकार का विरोध भी दर्शाया गया। वाहन रैली के लिए पुलिस परमिशन नहीं मिलने से पैदल रैली निकालकर पालिका कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया जबकि दोपहर के एक बजे ओलपाड तहसील के भांडूत गांव में घन कचरे के प्लान्ट के विषय पर रैली निकाली गई थी।

महान व्यक्तित्वों को अपमानित करना बंद करें कांग्रेस : पीएम मोदी

राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में रिमोट कंट्रोल से महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पर महान व्यक्तित्वों को अपमानित करने का आरोप लगाया। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भले उन्हें गाली दे सकती है, लेकिन वह महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल और बाबा साहेब आंबेडकर जैसी महान शि सयतों को अपमानित करना बंद करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता महात्मा गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने कहा कि उनकी चार साल की सरकार में स्वच्छता का दायरा बढ़ा है। कांग्रेस का नाम लिये बगैर मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी सिर्फ एक परिवार से बंधी है। उन्होंने कहा, 'लोग जाति, राज्य, चुनाव देखते हैं... महान शि सयतों को अपमानित करना बंद करें। मोदी अभी जीवित है, उसे 24 घंटे गाली दो और यह भी कम पड़ता है तो इसे 26 घंटे के लिये करो। कौन ना कह रहा है?' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया था कि गुजरात के सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा चीन बना रहा है, जिस पर भाजपा और गुजरात सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आयी थी।

विभिन्न प्रतिष्ठित हस्तियों के लिये स्मारक निर्माण को उचित ठहराते हुए मोदी ने कहा कि यह देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ने वालों के प्रति श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित 600 से अधिक घरों को लोगों को समर्पित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ महिला लाभार्थियों से बात की। मोदी ने कहा कि यह संग्रहालय का ना केवल राजकोट के लोगों बल्कि समूचे विश्व के लिये बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय से गांधीवादी संस्कृति, मूल्यों और दर्शन के बारे में जागरुकता फैलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनकी जयंती चार अक्टूबर को है, उन्होंने देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी। अगर हमलोग उनकी प्रतिमा बनाते हैं तो...यह हमारा लक्ष्य है कि देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ने वाले नयी पीढ़ी के लिये प्रेरणा के स्रोत बनें।

उन्होंने कहा, जब मैंने बाबा साहेब आंबेडकर की स्मृति में 'पंचतीर्थ' का निर्माण किया तो मुझे विश्वास था कि आने वाली पीढ़ी एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरित होगी जिसने गरीबी से बाहर निकलकर इस तरह तरक्की की और ऐसी ऊंचाई हासिल की। उन्होंने कहा कि हमने 'मिसाइल मैन' एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के गृहनगर में एक स्मारक बनाया, ताकि आगंतुक उनसे प्रेरणा ले सकें। संयुक्त राष्ट्र के 'चैंपियन्स ऑफ द अर्थ' स मान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े हकदार थे। मोदी संयुक्त राष्ट्र के ''चैंपियन्स ऑफ द अर्थ'' स मान से स मानित हुए हैं।

विधानसभा में गांधीजी की 150वीं जयंती पर पुष्पाजंलि दी जाएगी

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा में 2 अक्टूबर को गांधीजी की 150वीं जयंती के मौके पर पुष्पाजंलि दी जाएगी7 मंगलवार को सुबह 9 बजे गुजरात विधानसभा परिसर में गांधीजी की विशाल प्रतिमा को पुष्पांजलि देने के बाद विधानसभा गृह में उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पण किए जाएंगे।

अठवा में वीवर्स के साथ लाखों धोखाधड़ी

सूरत। शहर के अठवा में निवासी वीवर्स और उनके मित्र से 68.09 लाख का यार्न का माल खरीदने के बाद पेमेंट नहीं चुकाकर धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई है।

अठवा पुलिस सूत्रों अनुसार नानपुरा निवासी महेश मोतीराम गोदीवाला ने गत रोज माधवनंदन सोसायटी, कतारगाम निवासी हरेश गजेरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी। जिसमें महेश ने कहा कि आरोपी हरेश ने विश्वास में लेकर महेश के पास से 29,15,831 रूपए का डाइड यार्न का माल खरीदा था जिसमें से 7,79,311 रूपए का माल वापस देकर बाकी के 21,40,000 का माल अपने पास रखा था जबकि दोस्त हिरोइज रूस्तम गांधी के पास से 46,69,698 रूपए का टैक्स यार्न का माल समेत 68,09,698 रूपए का माल खरीदने के बाद पेमेंट नहीं चुकाकर धोखाधड़ी की। महेश गोदीवाला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

सूरत। खेल महाकुंभ 2018 में ड्रीम इंडिया स्कुल ने मारी बाजी। ड्रीम इंडिया स्कूल के चार लड़कियां और एक लड़का जिला लेवल पर सिलेक्ट हुआ। इन बच्चों को स्कूल परिवार और प्रिंसिपल पुनम उपाध्याय ने अभिनंदन दिया।

नवरात्री वेकेशन को लेकर स्कूलों में दुविधा की स्थिति

अहमदाबाद। राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नवरात्री वेकेशन की घोषणा कर दी है दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड के संलग्न स्कूल नवरात्री वेकेशन को लेकर अभी तक दुविधा में है। राज्य सरकार के निर्णय में सीबीएसई की स्कूल सहमत नहीं है, इसे लेकर नवरात्री वेकेशन को लेकर सीबीएसई स्कूलों में दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है।

गीर में शेर की मौत का आंकड़ा २१ पर पहुंचा : प्रशासन सक्रिय

उपचार के दौरान १४ शेर की मौत हुई और सात के शव मिलने के बाद मृतक २१ : हाल में ९ शेर उपचार के तहत : गुजरात सरकार भी आश्चर्य में

अहमदाबाद। जूनागढ़ के गीर क्षेत्र में दलखानिया और जसाधार रेन्ज में और पांच शेर के शव मिलने पर मौत का आंकड़ा २१ पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ अभी भी हालत बदतर हो चुकी है। शेरों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने पर अमेरिका से भी विशेष प्रकार की दवाईयां मंगायी जा रही है।देशभर में से विशेषज्ञों की टीमें भी पहुंच रही है। हाल में बड़ी संख्या में शेर उपचार के तहत है। दूसरी तरफ उपचार के दौरान १४ शेर की मौत हुई है। सात के शव मिले है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, हाल में नौ शेर की तबियत खराब होने की जानकारी मिल रही है। ११ से १९ सितम्बर के दौरान ११ शेरों की मौत हुई है जबकि २० से ३० सितम्बर के दौरान और १० शेर की मौत हुई है। बीमारी के कारण शेर की तबियत खराब होने का भी प्राथमिक तरीके से सामने आ रहा है। अभी तक में कुल २१ शेरों की मौत हुई होने का आखिर में राज्य के वन विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है और यह आधिकारिक आंकड़ा सोमवार को घोषित किया गया। गीर में २१ शेरों की मौत का सही मौत का आंकड़ा सामने आने पर चारों तरफ सनसनी मच गई। प्रकृतिप्रेमी काफी नाराज है। गीर क्षेत्र में शेरों की मौत को लेकर परिस्थिति गंभीर और संवेदनशील थी, फिर भी सरकार और वन विभाग द्वारा काफी गलत तरीके से छिपाने का प्रयास किया गया है लेकिन यह पूरे मामले में कोई जिम्मेदार यह सभी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ, गुजरात की राजनीति के वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला ने अब पूरे मामले में भाज पा सरकार पर निशाना साधा और बताया है कि, शेरों की मौत मामले में राज्य सरकार की सीधी और गंभीर लापरवाही और उदासीनता स्पष्ट हुई है। इस दौरान गीर क्षेत्र में अब २१ शेरों की मौत बाद अब सक्रिय हुई वन विभाग द्वारा देशभर में से प्राणी विशेषज्ञों और वन्य प्राणी चिकित्सकों को गीर बुलाने का निश्चित किया गया है। वन विभाग द्वारा घोषित किए गए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार १२ सितम्बर से के दौरान ११ शेरों की मौत दर्ज की गई थी। जबकि २० सितम्बर से ३० सितम्बर के दौरान १० शेरों की मौत दर्ज की गई थी। अभी तक में कुल २१ शेरों की मौत होने की बात स्पष्ट हो गई है। एक साथ इतने कम समय में २१ शेरों की मौत को लेकर अब सिर्फ गुजरात ही नहीं देशभर में सनसनी मच गई क्योंकि एशियाटीक लॉयन को लेकर गुज रात की अलग पहचान विश्वभर में बन रही है तब इसका अस्तित्व खत्म होने की वजह से वन्य और प्रकृतिप्रेमियों में शोक की लहर फैल चुकी है। शेरों की मौत मामले में अब परिस्थिति बेकाबू होने पर वन विभाग और राज्य सरकार द्वारा देशभर में से प्राणी विशेषज्ञों और वन्यप्राणी डॉक्टरों को बुलाने का निश्चित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास और सुलभ शौचालय योजना में लिया जा रहा सुविधा शुल्क

Pradhan Mantri Awaas Yojana

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के विकासखंड मांधाता के ग्राम पंचायत पूरे बसावन में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय योजना में ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद पांडे व ग्राम सेवक अखिलेश कुमार सरोज की मिलीभगत से लाभार्थियों से 500 10000 और 20000 रुपए सुविधा शुल्क के रूप में लिए जा रहे हैं प्रार्थी बालेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुझसे शौचालय के नाम पर ?500 रुपए सुविधा शुल्क के रूप में मांगा गया प्रार्थी ने मुख्य विकास अधिकारी व जिला अधिकारी के समक्ष आरटीआई जन सूचना अधिकार की धारा से संबंधित सूचना जानने का प्रयास किया ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम सेवक अखिलेश कुमार सरोज में शाम को लगभग 7:55 पर फोन करके कोर्ट में घसीट ने की धमकी दी बता दें कि ग्राम पंचायत पूरे बसावन में ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद पांडे जी हैं केले का कार्यभार उनके छोटे भाई अशोक कुमार पांडे जी देखते हैं इन्हीं के कार्य क्षेत्र की घटना है प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना में गड़बड़ी देखने को मिल रही है

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

फर्जी आधार कार्ड लगाकर दिए गए आवास

प्रतापगढ। विकासखंड मांधाता की ग्राम सभा जगदीशपुर में आवास बांटने के नाम पर व्यापक खेल खेला गया है अपात्र के फर्जी आधार कार्ड लगाकर निकालें लाखों रुपए ? ग्राम सभा जगदीशपुर के वर्तमान प्रधान जीतलाल पटेल व ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सरोज के कार्यकाल में यह घटना हुई संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी गई लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा ग्राम सभा जगदीशपुर में एक और धांधली सामने आई है ग्राम प्रधान व ग्राम सेवक की मिलीभगत से ग्राम सभा जगदीशपुर में ऐसे आदमियों को आवास बांट दिया गया जो इस दुनिया में है ही नहीं गांव के श्याम बाबू पटेल वह विजय कुमार की मानें तो दयाराम और रामनाथ कई वर्ष पहले दिवंगत हो गए थे ग्राम प्रधान व ग्राम सेवक ने ऐसा चमत्कार दिखाया की आज तक कोई नहीं दिखाया होगा उन्होंने मरे हुए व्यक्ति के नाम पर आवास आवंटित कर दिए और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी ग्राम सभा के लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आवास की लिस्ट निकाली तो ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक की पोल खुल गई प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना में व्यापक तरीके से घोटाला किया गया है वर्ष 2016 – 17 में मनोरमा. छोट का. रमेश चंद्र. प्रभादेवी. गायत्री देवी. लल्लू राम. नोखे लाल. और इस राजी. के नाम पर आवास के लिए धन राशि तो आई मगर इन लोगों को ना तो आवास मिला और ना ही रुपए मिले इन लाभार्थियों के लिए आवंटित 120000 रुपए किसे दिए गए यार आज कोई भी अफसर बोलने को तैयार नहीं है

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com